नईदुनिया

चीन की चुनौती : सड़क के रास्ते टैंक और सेना भेजने की साजिश

बीजिंग

पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के जरिए अरब सागर तक पहुँच बनाने के बाद, अब चीन की रणनीतिक नज़र बंगाल की खाड़ी पर टिकी है। बीजिंग ने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ एक नया आर्थिक कारिडोर बनाने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा दिए हैं। यदि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी होती है, तो चीन को भारत की पूर्वी सीमा के बेहद करीब सड़क, रेल और समुद्री संपर्क का एक ऐसा विशाल नेटवर्क मिल सकता है, जिसे भू-राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार इसके पूरा हो जाने के बाद, चीन ज़रूरत पड़ने पर सड़क के रास्ते भारत की पूरी पूर्वी सीमा तक अपने टैंक और सैनिक आसानी से भेज सकेगा, जिससे भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा के दौरान इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव है कि चीन के कुनमिंग शहर को म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों और खासकर मोंगला पोर्ट से जोड़ा जाए। यह नया गलियारा काफी हद तक सीपीईसी की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है, जिसने चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के ज़रिए अरब सागर तक पहुँच दी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी आधुनिक सड़क, रेल और बंदरगाह नेटवर्क शांति के समय व्यापार के लिए उपयोग होता है, लेकिन संकट या युद्ध की स्थिति में वही बुनियादी ढाँचा सैन्य साजो-सामान, सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों की तीव्र आवाजाही के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत के लिए यह चीनी प्रोजेक्ट चिंता का विषय है।ढाका में तैनात चीनी राजदूत याओ वेन ने बताया कि यह विचार बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि वर्ष 1999 में बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक कारिडोर की अवधारणा सामने आई थी, जिसका मकसद चारों देशों को सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई संपर्क से जोड़ना था, लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। याओ वेन ने कहा कि चीन और बांग्लादेश के बीच शुरू हो रहा सहयोग अंतिम पड़ाव नहीं है और अगर दूसरे देश भी इसमें शामिल होना चाहें तो चीन उनका स्वागत करेगा। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बीजिंग और ढाका के रिश्ते तेज़ी से मज़बूत हुए हैं। इस दौरान कई ऐसे समझौते हुए हैं, जिन पर भारत की नज़र बनी हुई है। इनमें तीस्ता नदी परियोजना, भारत की पूर्वी सीमा के पास लालमोनिरहाट एयरबेस के विकास में चीनी सहयोग, ढाका में ड्रोन निर्माण और टेक्नोलाजी ट्रांसफर यूनिट स्थापित करने की योजना के साथ-साथ मोंगला पोर्ट के पास आर्थिक क्षेत्र के विकास का ठेका चीन को दिया जाना शामिल है। खास बात यह है कि मोंगला प्रोजेक्ट पहले भारत के साथ प्रस्तावित था, जिसे बाद में बांग्लादेश ने रद्द कर चीन को सौंप दिया।

न्यूज ब्रीफ

नेपाल में सुशासन पर जोर, बालेन्द्र शाह सरकार के 100 दिन सकारात्मक बताए गए : रवि लामिछाने

काठमांडू। नेपाल के सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने कहा है कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती 100 दिन सुशासन और नागरिक सेवाओं में सुधार की दिशा में सकारात्मक रहे हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए लामिछाने ने कहा कि इस अवधि में सरकार का मुख्य फोकस सुशासन और जनता को सरल, पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने पर रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने, होम डिलीवरी सिस्टम विकसित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में काम शुरू किया गया है, ताकि आम लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिल सकें। लामिछाने के अनुसार, तुरंत दिखाई देने वाले परिणामों पर भी काम जारी है और सरकार सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर नीतियों में सुधार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी नए प्रशासन में प्रारंभिक चरण में कुछ प्रक्रियागत कमियां रह सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार उन्हें पहचानकर सुधार की दिशा में आगे बढ़े। उनके अनुसार, यदि भविष्य में कोई कमी सामने आती है तो उसे दोबारा न दोहराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सिंधु जल संधिः जल संकट में ड्रैगन को घसीट रहा पाकिस्तान, भारत के सख्त रुख के बाद नई कूटनीतिक चाल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान दशकों से सिंधु जल समझौते से लाभ उठा रहा था, अपनी प्यास बुझा रहा था, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीतियों ने भारत को सिंधु जल संधि पर अपने रुख की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद जारी रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि पर पहले जैसी व्यवस्था नहीं चल सकती। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान चीन की गोद में बैठकर कुदरत की सौगातों का पाठ पढ़ा रहा है। पाकिस्तान का तर्क है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं हैं, बल्कि चीन भी इनका एक बड़ा हितधारक है, और इस मुद्दे पर उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने अचानक चीन को जल सिंधू विवाद में क्यों घसीटा, यह समझना जरूरी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने हाल ही में कहा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कुदरत की देन हैं और ये सिंधु से लेकर मेकांग तक कई देशों को पानी देती हैं। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि चीन से भी कई बड़ी नदियां निकलती हैं, इसलिए पानी का मुद्दा पूरी मानवता से जुड़ा है और चीन की भूमिका भी इसमें अहम है। पाकिस्तान यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि यह सिर्फ भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का एक साझा मुद्दा है, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण पक्षकार है। ताहिर अंद्राबी ने अपने बयान में जोर दिया कि चीन का रुख पानी से जुड़े बड़े मुद्दों पर हमेशा सकारात्मक रहेगा, क्योंकि वह न सिर्फ दक्षिण एशिया में बहने वाली नदियों के मामले में, बल्कि हिमालय से चीन और सुदूर पूर्व की ओर बहने वाली विशाल नदी प्रणालियों के मामले में भी एक अहम पक्षकार है।

पूर्वी इंडोनेशिया के पास 6.2 तीव्रता का भूकंप, किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं

जकार्ता। पूर्वी इंडोनेशिया के नार्थ मलुकु प्रांत के पास शुक्रवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप में अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। तुर्किए की सरकारी संवाद एजेंसी अनाडोलू और इंडोनेशिया की चैनल न्यूज़ एशिया (सीएनए) के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 11:31 बजे टोबेलो से लगभग 58 किलोमीटर पश्चिम में आया। इसका केंद्र 120 किलोमीटर की गहराई पर था। झटके इतने तेज थे कि आसपास के क्षेत्रों में लोग कुछ सेकंड के लिए घबरा गए। भूकंप के केंद्र से करीब 114 किलोमीटर दूर स्थित टर्नेट शहर के निवासी ने बताया कि झटके के दौरान वे एक काफी स्टाल पर बैठे थे और अचानक कुर्सी हिलने लगी, जिससे उन्हें पिछले भूकंपों की याद आ गई। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी (बीएमकेजी) ने पुष्टि की है कि इस भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है। इंडोनेशिया रिंग आफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण भूकंप और ज्वालामुखीय घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।

चीन पर जापान की घेराबंदी : भारत की भूमिका पर विशेषज्ञ संशय में

टोक्यो

जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के दिल्ली दौरे ने वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। उनका दौरा तब हो रहा है जब जापान चीन के खिलाफ एक मुखर मोर्चा खोल चुका है और खुले तौर पर ताइवान का समर्थन कर रहा है, जिसके बाद चीन ने युद्ध की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मजबूत गठबंधन तैयार करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई दिल्ली इस चीनी-केंद्रित रणनीति के साथ कितनी गहराई से जुड़ने को तैयार है।

पीएम तकाइची ने भारत में रक्षा, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो-गैस जैसे कई अहम क्षेत्रों में समझौते किए हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि समझौतों के पीछे उनका प्राथमिक मकसद उन देशों को एकजुट करना है जो इंडो-पैसिफिक में बीजिंग के प्रभुत्व से चिंतित हैं। इसके साथ ही, यह दौरा उन्हें घरेलू स्तर पर भी एक आसान जीत दिला सकता है, क्योंकि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही जापानी जनता के बीच उनका समर्थन दर गिरा है। वासेडा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बेन एस्कियोन ने जोर दिया कि तकाइची जापान की सुरक्षा नीतियों में तेजी लाना चाहती हैं और भारत को इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाना चाहती हैं।

हालांकि, भारतीय विशेषज्ञ इस बात पर संशय रखते हैं कि भारत जापान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। एस्कियोन के अनुसार, टोक्यो का फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक अभियान भारत को चीन के मुकाबले करीब लाने पर केंद्रित है, लेकिन भारत की इसमें शामिल होने की इच्छा चीन के साथ उसके अपने संबंधों पर निर्भर करती है। उनका मानना है कि जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता है, नई दिल्ली अमेरिका और जापान के साथ सहयोग करने को अधिक तैयार होती है, लेकिन जब रिश्ते स्थिर होते हैं, तब उसकी यह तत्परता घट जाती है। वर्तमान में, चीन के साथ भारत के रिश्ते स्थिर माने जा रहे हैं, इसलिए तत्काल पूर्ण समर्थन की संभावना कम है।

अपनी यात्रा के दौरान, तकाइची ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया, जिसमें आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा

टेलीस्कोप की मदद से किया ब्रह्मांड की दुर्लभ घटना का अवलोकन

वाशिंगटन। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की दुर्लभ घटना का अवलोकन किया है। इन दुर्लभ घटनाओं में छह विशाल गैलेक्सियां आपस में मिलकर एक महाविशाल आकाशगंगा का निर्माण करती दिखाई दे रही हैं। इस प्रक्रिया के केंद्र में एक तेजी से विकसित होता महाविशालकाय ब्लैक होल भी मौजूद है, जो वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय बना हुआ है। यह खोज अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने की है, जिसमें लीडेन विश्वविद्यालय और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शामिल हैं। अध्ययन में जिस खगोलीय संरचना का अवलोकन किया गया है, उसे टीजीएसएसजे1530+1049 नाम दिया गया है। यह प्रणाली पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक इसे उस समय की स्थिति में देख रहे हैं जब ब्रह्मांड की आयु केवल लगभग 1.5 अरब वर्ष थी। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का अध्ययन इसलिए शुरू किया था क्योंकि पहले किए गए रेडियो अवलोकनों में यहां एक सक्रिय महाविशाल ब्लैक होल होने के संकेत मिले थे। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्राप्त नई तस्वीरों और आंकड़ों ने कहीं अधिक जटिल और रोमांचक तस्वीर पेश की। शोधकर्ताओं को यहां केवल एक गैलेक्सी नहीं, बल्कि कम से कम छह गैलेक्सियों का समूह दिखाई दिया, जिनमें से चार पहले से ही अत्यंत विशाल हैं। इन गैलेक्सियों में अरबों सूर्यों के बराबर तारकीय द्रव्यमान मौजूद है और वे एक-दूसरे के बेहद करीब स्थित हैं।

जैसे मुद्दे शामिल थे। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर संयंत्रों में निवेश सहित भारतीय टेक्नोलाजी फैब्रिकेशन में सहयोग बढ़ाने की बात की है, जिसका लक्ष्य चिप्स और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी डालर के बजाय रुपये और येन में द्विपक्षीय व्यापार करने पर भी चर्चा हुई, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।

जानकार भी मानते हैं कि जापानी नेता की मुख्य चिंता चीन से उत्पन्न खतरा है। वे चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहती हैं। जापान अन्य एशियाई देशों जैसे फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भी रक्षा क्षमताएं बढ़ा रहा है, जो साउथ चाइना सी पर बीजिंग के दावों से जूझ रहे हैं। यह चीन विरोधी गठबंधन बनाने की जापान की व्यापक विदेश नीति का हिस्सा है। हालाँकि, भारत का पूर्ण समर्थन इस भू-राजनीतिक समीकरण में अभी भी एक खुला प्रश्न बना हुआ है।

तक्षशिला में पुनर्निर्माण को लेकर यूनेस्को ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

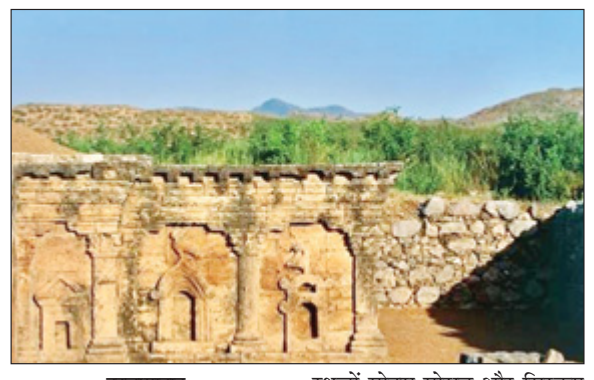

इस्लामाबाद

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने पाकिस्तान को विश्व धरोहर स्थल तक्षशिला में दो प्राचीन स्मारकों पर किए गए पुनर्निर्माण कार्य को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। एजेंसी ने कहा है कि यदि निर्माण कार्य को मूल स्वरूप के अनुरूप बहाल नहीं किया गया, तो तक्षशिला को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा सकता है और उसकी विश्व धरोहर का दर्जा भी प्रभावित हो सकता है।

रूस की अंतरराष्ट्रीय सरकारी समाचार टेलीविजन नेटवर्क रूस टुडे (आरटी) ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि यूनेस्को ने हाल ही में पाकिस्तान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक स्थलों पर अनावश्यक बदलाव उनकी प्रामाणिकता और ऐतिहासिक अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। एजेंसी ने जर्मनी के एक विश्व धरोहर स्थल का उदाहरण भी दिया, जिसे इसी तरह के कारणों से सूची से हटाया गया था।

यूनेस्को ने विशेष रूप से तक्षशिला के दो प्रमुख पुरातात्विक स्थलों मोहरा मोराडु और सिरकप पर किए गए पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताई है। एजेंसी का कहना है कि इन कार्यों से स्मारकों का मूल स्वरूप प्रभावित हुआ है।

मामला तब सामने आया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने पेरिस स्थित यूनेस्को में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि को तस्वीरों और दस्तावेजों के माध्यम से इन निर्माण कार्यों की जानकारी भेजी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पंजाब पुरातत्व विभाग ने कई स्थानों पर मूल प्राचीन दीवारों की जगह नया निर्माण किया और कुछ हिस्सों की ऊंचाई भी बढ़ा दी।

शिकायत मिलने के बाद यूनेस्को की टीम ने तक्षशिला का दौरा कर स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एजेंसी ने पाकिस्तान से पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा कर उसे मूल स्वरूप के अनुरूप बहाल करने का आग्रह किया है।

तक्षशिला प्राचीन काल का एक प्रमुख शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र रहा है, जिसकी ऐतिहासिक विरासत छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1980 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया था।

कजाकिस्तान में छिपे टंगस्टन खजाने पर ट्रंप की है नजर, चीन-रूस हैं अपना बनाना

वाशिंगटन। आधुनिक विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक ऐसा धातु है जिसके बिना अंतरिक्ष यात्राओं से लेकर हमारे घरों के बल्ब तक सब अधूरा है- इसका नाम है टंगस्टन। यह अद्भुत और खास धातु कजाकिस्तान में छिपी हुई है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। रसायन विज्ञान के छात्र इसे डब्ल्यू प्रतीक और 74 परमाणु संख्या से जानते हैं और इसे वोल्फ्राम भी कहा जाता है। अमेरिका के साथ ही चीन और रूस जैसी महाशक्ति भी इसे अपना बनाना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल, पिछले साल नवंबर में जब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव वाशिंगटन दौरे पर आए थे, तब अमेरिका और कजाकिस्तान के बीच एक अहम समझौता हुआ था। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनी कोव काज कैपिटल ग्रुप को कजाकिस्तान की सरकारी माइनिंग फर्म के साथ एक जाइंट वेंचर में 70 फीसदी हिस्सेदारी दी गई। इस परियोजना से अमेरिका को हर साल हजारों मीट्रिक टन टंगस्टन मिलने की उम्मीद है, जिससे उसे चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

म्यांमार की सीमा पर युद्ध जैसे हालात बांग्लादेश में शरणार्थी संकट की आशंका

ढाका

म्यांमार के रखाइन राज्य में तेज होती सैन्य झड़पों के बीच बांग्लादेश-म्यांमार सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सीमा से लगे टेकनाफ और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आशंका है कि हिंसा के कारण रोहिंग्या शरणार्थियों की एक नई लहर बांग्लादेश की ओर रुख कर सकती है। स्थानीय निवासियों और रखाइन में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के अनुसार, पिछले दो दिनों से सीमा पार लगातार भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि म्यांमार की सेना ने मौंगडाव, बुथिडांग और अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में अपने सैन्य अभियान तेज़ कर दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र शाह पोरिर द्वीप के निवासी शाह आलम ने बताया कि विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि घर भूकंप जैसी तीव्रता से हिलने लगे। हालांकि, बांग्लादेशी अधिकारियों ने उन खबरों की पुष्टि नहीं की है जिनमें दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या नाफ नदी के किनारे बांग्लादेश में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

काक्स बाज़ार के बालूखाली शरणार्थी शिविर

के एक रोहिंग्या सामुदायिक नेता ने बताया कि मौंगडाव में स्थिति बेहद गंभीर है और कई परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। बांग्लादेश में पहले से ही 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जो म्यांमार में वर्षों से जारी हिंसा, विशेषकर 2017 के बड़े पलायन के दौरान, अपने घर छोड़कर आए थे। ऐसे में रखाइन में फिर से बढ़ती हिंसा ने सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। टेकनाफ उपज़िला प्रशासन ने कहा है कि अब तक किसी नई घुसपैठ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, बार्डर गार्ड बांग्लादेश ने नाफ नदी और अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। इस बीच, म्यांमार की सीमा पर बढ़ते संघर्ष का असर थाईलैंड पर भी पड़ा है। म्यांमार की सेना और करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच संघर्ष के दौरान सीमा पार से हुई गोलीबारी में थाईलैंड के टाक प्रांत में कुछ घर क्षतिग्रस्त होने के बाद थाई प्रशासन ने सभी सीमा पार मार्ग अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं।

लिथुआनिया में परमाणु हथियारों पर लगी संवैधानिक रोक हटाने का प्रस्ताव, संसद में संशोधन बिल पेश

विनियस

यूरोपीय देश लिथुआनिया की संसद (सेइमास) में परमाणु हथियारों की तैनाती पर लगी संवैधानिक रोक हटाने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव को संसद के 141 में से 51 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जिससे इसे औपचारिक रूप से संसद में दर्ज कराया गया है।

प्रस्ताव के तहत संविधान के अनुच्छेद 137 को समाप्त करने की मांग की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार, लिथुआनिया में बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों और विदेशी सैन्य ठिकानों की तैनाती पर प्रतिबंध है।

यह पहल राष्ट्रपति गितानास नौसेदा के उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस संवैधानिक प्रावधान को पुराना बताते हुए कहा था कि बदलते सुरक्षा हालात में देश को भविष्य के विकल्प खुले रखने चाहिए। संसदीय दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद नौसेदा ने कहा कि अधिकांश राजनीतिक दल अनुच्छेद 137 को पूरी तरह हटाने के पक्ष में हैं।

राष्ट्रपति का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और लिथुआनिया को नाटो के भीतर किसी कमजोर कड़ी या ग्रे ज़ोन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने फिनलैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि नाटो में शामिल होने के बाद वहां भी परमाणु हथियारों से जुड़े प्रतिबंधों में बदलाव किया गया है।

हालांकि, रूस ने लिथुआनिया और अन्य बाल्टिक देशों द्वारा जताई जा रही सुरक्षा चिंताओं को खारिज किया है। मास्को का कहना है कि नाटो देशों पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है और रूस के कथित खतरे का हवाला देकर पूर्वी यूरोप में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई जा रही है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका नाटो के पूर्वी हिस्से के कुछ देशों में अपने परमाणु हथियारों की संभावित तैनाती पर विचार कर रहा है। रूस की सीमा से लगे कई देशों ने ऐसी तैनाती में रुचि भी दिखाई है।

यूरोप में बढ़ते सैन्यीकरण के बीच नाटो नेतृत्व सदस्य देशों से अपनी रक्षा तैयारियां मजबूत करने की अपील कर रहा है। वहीं रूस ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी सीमाओं के निकट नाटो का परमाणु ढांचा स्थापित किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष सैन्य खतरे के रूप में देखा जाएगा और उसके अनुरूप जवाब दिया जाएगा। साथ ही, रूस ने यह भी कहा है कि वह नाटो के साथ समानता के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है।